भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2094

सोमवार, 09 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

प्रवासी मजदूरों का कल्याण

2094. श्री राजकुमार रोत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से गुजरात राज्य के अहमदाबाद, और सूरत जैसे बड़े शहरों में कार्य करने के लिए आने वाले श्रमिकों के आवास और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बड़े शहरों में कार्य करने वाले श्रमिक अपने साथ अपने छोटे बच्चों को भी लाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इन प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(घ) बड़े शहरों में कार्य करने वाले श्रमिकों की कार्य के दौरान दुर्घटना होने की स्थिति में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ) प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए, अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 में अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों की लाइसेंसिंग आदि का प्रावधान है। नियोजित कामगारों को आवासीय सुविधा और चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित है। इस अधिनियम को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में शामिल किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने प्रवासी कामगारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना, किफायती किराये के आवास परिसर (एआरसीएच) की भी शुरूआत की है।

बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत यह अधिदेशित है कि समुचित सरकार को किसी निकटवर्ती स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी होगी, जो अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों के बच्चों पर भी लागू होती है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को मृत्यु होने पर मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है। इस अधिनियम को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल किया गया है।

******